दैनिक जागरण

प्रेम हर बोझ को हल्का बना देता है

यह तो होना ही था

कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उस पर शायद ही किसी को हैरत हो। सत्ताधारी गठबंधन जद-एस और कांग्रेस के 11 विधायक जिस तरह इस्तीफा देकर राज्य के बाहर निकल गए उससे यह स्पष्ट है कि वह अपना फैसला बदलने वाले नहीं हैं। इन 11 विधायकों के साथ जद-एस और कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले विधायकों की कुल संख्या 14 पहुंच गई है। कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को अल्पमत में आता देखकर भाजपा ने जिस तरह अपनी सक्रियता बढ़ा दी है उससे यह साफ हो जाता है कि ये इस्तीफे क्यों दिए गए हैं? कहना कठिन है कि कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन कब और कैसे होता है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुमारस्वामी सरकार पहले दिन से ही अस्थिर नजर आ रही थी। इसकी एक बड़ी वजह जद-एस और कांग्रेस की ओर से केवल सत्ता के लिए दोस्ती कायम करना था। इस दोस्ती का एकमात्र उद्देश्य भाजपा को सत्ता से बाहर रखना था। यह दोस्ती अवसरवाद की राजनीति का परिचायक ही थी, क्योंकि भाजपा, कांग्रेस और जद-एस एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। विधानसभा चुनावों में भाजपा पहले नंबर पर आई, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। बहुमत जुटाने की उसकी कोशिश नाकाम रहने पर कांग्रेस के समर्थन से जद-एस के नेतृत्व में गठबंधन सरकार ने सत्ता संभाली, लेकिन दोनों में खटपट जारी रही। इसकी गिनती करना कठिन है कि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कितनी बार अपना दुखड़ा रोया? लगता है कांग्रेस ने या तो यह समझने की कोशिश नहीं की कि उन्हें सरकार चलाने में क्या कष्ट हो रहा है या फिर उसने उसे दूर करना जरूरी नहीं समझा।

कुमारस्वामी सरकार बेमेल गठबंधन वाली पहली सरकार नहीं। इस तरह की सरकारें पहले भी बनती रही हैं और उनमें से ज्यादातर अपना कार्यकाल पूरा करने में नाकाम भी रही हैं। ऐसी सरकारें तब अवश्य ही नाकामी का शिकार होती हैं जब वे बिना किसी साझा कार्यक्रम के चलती हैं। येन-केन-प्रकारेण सत्ता में बने रहने का मकसद भी उन्हें ले डूबता है। ऐसी सरकारें शायद ही कभी जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर पाती हों, लेकिन वे इसलिए बनती हैं, क्योंकि त्रिशंकु सदन की स्थिति में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं रहता कि एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े दल एक साथ आएं या फिर उनमें तोड़फोड़ हो। कर्नाटक इसकी ही गवाही दे रहा है। यहां पहले जनादेश को किनारे कर बेमेल गठबंधन बना और अब यह गठबंधन टूट-फूट से दो-चार हो रहा है। पता नहीं इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन हमारे नीति-नियंता यह समझें तो बेहतर कि कर्नाटक की जनता ने इस इरादे से मतदान नहीं किया था कि चुनाव बाद जद-एस और कांग्रेस एक साथ आकर सरकार बना लें। स्पष्ट है कि इस सवाल का जवाब तलाशने की सख्त जरूरत है कि त्रिशंकु सदन की स्थिति में सरकार का गठन कैसे हो? इस सवाल का यह जवाब नहीं हो सकता कि किसी को बहुमत न मिलने की स्थिति में नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। एक तो दोबारा चुनाव के बाद त्रिशंकु सदन से मुक्ति मिलना आवश्यक नहीं और दूसरे, मध्यावधि चुनाव सरकारी खजाने पर बोझ ही डालते हैं।

ग्रीन बोनस की दरकार

उत्तराखंड को अस्तित्व में आए 18 साल हो गए, मगर पर्यावरणीय सेवाओं के एवज में ग्रीन बोनस की उसकी साध अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। वह भी तब, जबकि राज्य की ओर से इस सिलसिले में केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है। यह बात अलग है कि विभिन्न अवसरों पर केंद्र ने राज्य के तर्क को स्वीकारा जरूर है, मगर ग्रीन बोनस के मामले में उत्तराखंड की झोली अब तक खाली ही है। दरअसल, 71 फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड की परिस्थितियां भी विषम हैं। बावजूद इसके तमाम दिक्कतें झेलने के बाद भी पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर जंगलों को सहेजने में सूबा अहम भूमिका निभा रहा है। सरकारी आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। हालिया सर्वे पर ही नजर दौड़ाएं तो उत्तराखंड हर साल तीन लाख करोड़ से अधिक की इको सिस्टम सर्विसेज दे रहा है। इन पर्यावरणीय सेवाओं में अकेले जंगलों का ही योगदान एक लाख करोड़ के आसपास है। वह भी तब जबकि राज्य और राज्यवासी लगातार वन कानूनों की बंदिशों की मार झेल रहे हैं। वन कानूनों के कारण यहां के विकास पर भी असर पड़ा है। सड़क, पेयजल, विद्युत से जुड़ी तमाम योजनाएं वन कानूनों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। उस पर जंगली जानवरों के खौफ ने जीना दुश्वार किया हुआ है। खासकर, पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां न घर आंगन सुरक्षित हैं और न खेत-खलिहान। स्थिति ये है कि राज्य में अब तक 600 से ज्यादा लोग वन्यजीवों के हमलों में जान गंवा चुके हैं, जबकि इसके चार गुना से अधिक घायल हुए हैं। यही नहीं, फसलों को भी वन्यजीव तबाह कर रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ही राज्य की ओर से ग्रीन बोनस मांगा जा रहा है, ताकि क्षति की कुछ भरपाई हो सके। हाल में मुख्यमंत्री इस बारे में नीति आयोग के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष राज्य का पक्ष रख चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही इस दिशा में कुछ एलान करेगी, मगर आम बजट में इसे लेकर मायूसी हाथ लगी। ग्रीन बोनस को लेकर इंतजार और बढ़ गया है। अब राज्य के समक्ष चुनौती यह है कि वह ग्रीन बोनस के मसले पर केंद्र के समक्ष अपने पक्ष को पूर्ण औचित्य के साथ सिद्ध करे।

बजट के लक्ष्य पाने की चुनौती

संजय गुप्त

कर संग्रह की मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए इसकी उम्मीद कम है कि जीएसटी एवं अन्य करों के जरिये आवश्यक राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है

प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार के आम बजट में बड़े सुधारों की उम्मीद की जा रही थी। इस उम्मीद की एक अन्य वजह यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कुछ समय से देश को पांच लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की बातें कर रहे हैं। इसका जिक्र आर्थिक सर्वे में भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद आम बजट के जरिये कोई बड़ा और क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया गया। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने बड़े कदम उठाने के बजाय छोटे-छोटे कदमों के जरिये ही आगे बढ़ने का फैसला किया और शायद इसी कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश आम बजट के प्रति जनता के एक बड़े वर्ग में उत्साह नहीं दिख रहा है। यह बजट इसकी सूचना दे रहा है कि मोदी सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को निरंतरता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बही-खाता की संज्ञा वाले आम बजट में एक ओर जहां गांव-गरीबों की चिंता की गई है वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे के विकास एवं विस्तार पर अगले पांच वर्षों में सौ लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च करने का संकल्प भी लिया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास और विस्तार की चिंता करने के साथ ही जिस तरह ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है उससे यह साफ है कि मोदी सरकार बजट के माध्यम से यह संदेश देना चाह रही थी कि नए भारत के निर्माण के क्रम में ग्रामीण आबादी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसकी प्राथमिकता में हैं। इसकी जैसी झलक आम बजट में पेश की गई है उसे देखते हुए कम से कम यह तो नहीं ही कहा जा सकता कि गांव और गरीब इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं हैं। चूंकि बजट के जरिये अति अमीर वर्ग पर टैक्स बढ़ाए गए हैं इसलिए विपक्ष की ओर से इस तरह की जुमलेबाजी के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई है कि यह तो सूट-बूट की सरकार है।

आम बजट में जिस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर विशेष बल दिया गया है उससे यह भी प्रकट होता है कि सरकार निर्धन तबके को सहारा देकर सबल बनाना चाह रही है। इसका प्रमाण ग्रामीण क्षेत्र में रोजी-रोजगार बढ़ाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों से भी मिलता है और किसानों के बीच सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने वाले प्रावधानों से भी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने और पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने जैसी योजनाएं यह बता रही हैं कि मोदी सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष के साथ अपने शेष कार्यकाल के लिए भी विकास का खाका खींचना चाह रही थी। इसका पता इससे चलता है कि सरकार ने हर क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान देने की कोशिश की है। बजट के जरिये बीमा और उड्डयन क्षेत्र को विदेशी पूंजी निवेश के लिए खोलने का जो निर्णय लिया गया वह उतना ही समय की मांग के अनुरूप है जितना श्रम सुधारों और विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प। देखना यह होगा कि ये संकल्प सही तरह पूरे हो पाते हैं या नहीं?

यह साफ है कि सरकार पर रोजगार के अवसर बढ़ाने और कारोबार जगत को बल देने का दबाव है। कारोबार जगत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने छोटी और मझोली कंपनियों को टैक्स में बड़ी राहत दी है। अब 400 करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत कारपोरेट टैक्स ही लगेगा। अब तक यह सुविधा 250 करोड़ रुपये सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को ही प्राप्त थी। केंद्र के इस कदम के बाद अब 99.3 प्रतिशत कंपनियां कारपोरेट टैक्स की 25 प्रतिशत की स्लैब में आ जाएंगी, लेकिन बात तब बनेगी जब ये कंपनियां तेजी से आगे बढ़ें। ध्यान रहे बैंकों की ओर से लघु एवं मझोले उद्योगों को दिए जाने वाले कर्ज की रफ्तार कोई बहुत उत्साहजनक नहीं। तथ्य यह भी है कि पिछले एक वर्ष में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी की खराब हालत के चलते छोटे-मझोले उद्योगों को कर्ज मिलना मुश्किल हो गया है। इस मुश्किल को आसान बनाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि राजस्व संग्रह में किसी भी तरह की कमी राजकोषीय घाटे को बढ़ा सकती है।

अवधेश राजपूत

इसमें दोराय नही कि देश के चहुंमुखी विकास का खाका खींचना समय की मांग थी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए जितने धन की जरूरत है उतना सरकार को हासिल नहीं हो पा रहा है। चिंता की बात यह है कि जीएसटी से उतना टैक्स नहीं मिल पा रहा है जितना अपेक्षित है। इसका मतलब है कि व्यापारियों का एक वर्ग अभी भी दो नंबर के तौर-तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। लगता है कि यह पुरानी आदत आसानी से नहीं छूटने वाली। इस आदत के न छूटने की एक वजह टैक्स अधिकारियों की उन व्यापारियों से मिलीभगत नजर आती है जो नई टैक्स व्यवस्था से बचे रहने के जतन करने में लगे हैं। बजट में ऐसे कोई उपाय नहीं दिख रहे जो दो नंबर से व्यापार करने वाले उद्यमियों को टैक्स देने के लिए प्रेरित कर सकें। कर संग्रह की मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए इसकी उम्मीद कम है कि जीएसटी एवं अन्य करों के जरिये आवश्यक राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। संभवतः इसी कारण एक ओर जहां विभिन्न उपकर एवं अधिभार बढ़ाए गए हैं वही मध्यवर्ग को कोई राहत भी नहीं दी गई है। वित्तमंत्री ने करदाताओं के योगदान के लिए उनका धन्यवाद करते हुए सरकारी खजाना भरने के लिए करोड़पतियों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया है। अब जहां दो करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये तक सालाना आय वाले व्यक्तियों पर अधिभार बढ़कर 25 प्रतिशत और पांच करोड़ रुपये से अधिक सालाना आय वालों पर अधिभार बढ़कर 37 प्रतिशत हो जाएगा।

समर्थ लोगों को अधिक टैक्स देना ही चाहिए, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान देना होगा कि भारत में लोगों की मानसिकता कम से कम टैक्स देने या फिर उससे बचे रहने की है। अति अमीरों को अधिक टैक्स के दायरे में लाने की पहल बड़े कारोबारियों को भारी-भरकम वेतन एवं लाभांश लेने से तो हतोत्साहित कर सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इस धन का इस्तेमाल कारोबार को विस्तार देने में हो। अगर ऐसा होता है तो सरकार के इरादे पूरे होने वाले नहीं। अति धनाढ्य वर्ग भले ही बहुत प्रभावी हो, लेकिन वह एक छोटा तबका ही है, इसलिए इसमें संदेह है कि उससे उतना टैक्स हासिल हो सकेगा जितने कि अपेक्षा की जा रही है। सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां भी टैक्स दरें ऊंची होती हैं वहां टैक्स से बचने की आदत भी पनपती है। टैक्स न देने या फिर बचाने की आदत का मुकाबला टैक्स नियमों को कठोर बनाने और टैक्स अधिकारियों की सख्ती के जरिये करने से यह भी हो सकता है कि अति अमीर कारोबारी टैक्स व्यवस्था के दबाव से घिर जाएं। अगर ऐसा होता है तो फिर कारोबार जगत को गति देना कठिन हो सकता है।

response@jagran.com

संकट में अवसर की खोज करने वाले

हास्य-व्यंग्य

सूर्यकुमार पांडेय

तालाब के पानी जैसा ठहराव उन्हें नापसंद है। वह नदी-नहर के पानी जैसा निरंतर बहते रहने के हिमायती हैं

भाई साहब हमारे कस्बे के भगीरथ कहे जाते हैं। दूर-दराज के इलाकों में भी उनके ही टैंकर पानी पहुंचाते हैं। वह विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। जब भी मिलते हैं, अपनी अंजुरी फैलाए हुए मिलते हैं। उनके होंठों से सदैव अजीब किस्म की प्यास टपकती रहती है। वह ताल, तलैया, पोखर, नदी और यहां तक कि समंदर को भी सोखने की शक्ति रखते हैं। नहरों और रजबहों की तो खैर उनके आगे औकात ही क्या है? छोटी-मोटी जलधाराएं तो उलटा उनसे ही पानी की गुहार लगाती हैं। वह चीज ही कुछ ऐसी हैं कि स्वयं प्याससंपन्न होते हुए भी बड़ों-बड़ों को पानी पिला देने की क्षमता रखते हैं। इतना ही नहीं, हमारे इलाके के सभी लोग इस बात से भी वाकिफ हैं कि भाई साहब सरेराह किसी को भी पानी-पानी कर सकते हैं। हालांकि वह घाट-घाट का पानी पी चुके हैं, तब भी जहां कहीं पर चुल्लू भर पानी दिख जाता है तो वह वहां पर अपना मुंह सबसे पहले आगे कर देते हैं।

पानी के मामले में वह समदर्शी हैं। गटर का पानी हो अथवा मिनरल वाटर, वह दोनों पर समान दृष्टि रखते हैं। कोई हाथ लगाए, उससे पहले वह अपना दावा ठोक देते हैं। द्रवित होना तो कोई उनसे सीखे। देश-प्रदेश में जिस भी दल की सरकार होती है, वह उसी पार्टी के खेमे की ओर बह जाते हैं। द्रव बनने के मामले में वह ठोस होने की काबिलियत रखते हैं। भाई साहब का मानना है कि इस धरती पर मूर्ख ही प्यासे रहते हैं। ज्ञानी तो वह होता है जो रेगिस्तान के बीच में खड़ा होकर भी अपनी खातिर नखलिस्तान तलाश लेता है। उनका स्वभाव भी जल जैसा ही तरल है। जब जिस पात्र में रहे, वैसा ही आकार ग्रहण किया। जब भी जिससे मिले, उसकी कृपा के जल से नहाकर ही लौटे। कुएं के पानी जैसा ठहराव उन्हें नापसंद है। वह नदी-नहर के पानी जैसा निरंतर बहते रहने के हिमायती हैं। हालांकि भाई साहब इससे भलीभांति अवगत हैं कि नहर में जरूरत के वक्त ही पानी छोड़ा जाता है। इसलिए वह हमेशा ऐसे ही किसी अनुकूल अवसर की तलाश में लगे रहते हैं। वक्त-जरूरत पड़ने पर अपनी आंखों में पानी भर लेने की कला हमारे इन भाई साहब से सीखी जा सकती है। उन्हें नाली के पानी की तरह बहने से भी कोई गुरेज नहीं है, बशर्ते इसमें निजी लाभ की संभावना दिखलाई पड़ती हो! मीडिया वालों को देखते ही उनके मुंह मे पानी सा आ जाया करता है। गोया औरों को पानी पर चढ़ाने और खुद बहती गंगा में हाथ धोने में वह सिद्धहस्त हैं।

भाई साहब की इस कला की ख्याति का आलम है कि यदि वह नदी के तट पर जाकर बस खड़े भर हो जाएं तो संभव है कि उसके किनारे खुद दो-चार सेंटीमीटर अंदर खिसक जाएं। वह लहर गिनकर पैसे कमाना जानते हैं। लहरें उठें या न उठें, भाई साहब में उन्हें भी पैदा करने की सामर्थ्य है। वैसे भी, चुनाव वगैरह के टाइम वह किसी के भी पक्ष में लहर मोड़ने में मैनेजमेंट के उस्ताद समझे जाते हैं। ऐसे मौकों पर वह खाने के साथ पीने का प्रबंध करने में माहिर हैं। उनकी यही कला उन्हें सदाबहार बनाए रखती है।

भाई साहब की गिनती इलाके के पानीदार लोगों में होती है। इसीलिए जब हमारे यहां पानी की समस्या हो गई तो सभी को सबसे पहले भाई साहब याद आए। जब से प्रधानमंत्री ने अपनी 'मन की बात' में जल संरक्षण पर खासा बल दिया है, भाई साहब भी लहालोट हैं। अब वह 'पानी बचाओ' अभियान की अगुआई कर रहे हैं। जल-संकट का निदान करने से पुण्यलाभ का उन्होंने हिसाब लगा लिया है। यह तो पीढ़ियों को तारने का काम है। सूखे में नाव चलाने की उनकी बरसों की अतृप्त कामना कंठ के मार्ग से झरने की मानिंद फूट पड़ी है। पिछले हफ्ते भाई साहब ने वाणी को और अधिक धाराप्रवाह बनाते हुए कहा था, 'आज से मैं नाम से ही नहीं, अपने काम से बनूंगा इस कस्बे का नया भगीरथ।' और अब भगीरथ बनने की दिशा में उनके प्रयास अपना रंग भी दिखलाने लग गए हैं।

कल ही कस्बे के मेन मार्केट में भाई साहब के भांजे की हैंडपंप की होलसेल एजेंसी खुल गई है। उनका कहना है कि इसके जरिये वह जल को शक्ति देने का काम कर रहे हैं। वह ऐसी ही बातें करते हैं और कभी-कभी तो यह दावा करने लगते हैं कि उनके पुरखों ने ही पानीपत का युद्ध भी लड़ा था। यदि भविष्य में उनके विरोधियों ने उनके किए-कराए पर पानी नहीं फेरा तो कल को यह भी हो सकता है कि हमारे कस्बे के लिए प्रस्तावित नई पानी की टंकी के निर्माण का ठेका भी उनके ही किसी रिश्तेदार के पास होगा। ऐसी विकट संभावना से भी इसलिए इन्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह हर संकट में अपने लिए अवसर खोज लेते हैं।

response@jagran.com

ऊर्जा

कर्मकांड और अध्यात्म

इस संसार में चार प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। अर्थार्थी तथा आर्त अपनी मनोकामना की पूर्ति तथा जीवन में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए परमात्मा की आराधना करते हैं जबकि जिज्ञासु सत्य को जानने के लिए उत्सुक होकर आगे बढ़ता है। ज्ञानी मनुष्य सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर भक्ति में प्रवृत्त होता है। वर्तमान में भक्ति व ज्ञान के मर्म को न समझकर लोग वाह्य क्रियाओं व आडंबरों के माध्यम से इस दिखावे में लगे रहते हैं कि वे कितने उच्च कोटि के ज्ञानी, भक्त व संत हैं। वे ऐसे आचरण करते हैं कि मानो पूर्ण पवित्र गए हों। इतने पवित्र कि यदि किसी मनुष्य का स्पर्श भी हो जाए तो स्नान किए बिना तसल्ली नहीं होती। कुछ ललाट पर त्रिपुंड या टीका लगाकर तथा गले में कई तरह की मालाएं डालकर अपनी धार्मिकता का प्रमाण देते हैं। इन वाह्य आडंबरों से सच्ची भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती और न ही कोई आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है।

मनुष्य को चाहिए कि वह परमात्मा की सच्ची भक्ति करके आध्यात्मिक उन्नति करे। स्वयं का उद्धार करने के लिए अग्रसर हो तभी वह इस भवसागर से पार हो सकेगा अन्यथा जन्म-मरण के चक्र में फंसा रहेगा। जीवन रहते मनुष्य संसार में पैदा होने की सार्थकता के संबंध में बार-बार विचार करे और यह भी विचार करे कि उसका यह जीवन बहुमूल्य है तभी भगवान की भक्ति कर स्वयं के अविनाशी स्वरूप को जानने की ओर पग बढ़ाया जा सकता है। मनुष्य को यह पता नहीं होता कि कब इस शरीर से उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा। कब मृत्यु आकर उसे दबोच लेगी। बड़े पुण्य से मानव देह की प्राप्ति का यह संयोग बना है। तो क्यों न भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान व परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्राणपण से जुटा जाए। यहां यह स्मरण करना होगा कि मां के गर्भ में बार-बार वह परमात्मा से प्रार्थना करता रहता था कि अब मनुष्य जन्म पाकर इस जीवन को आपकी भक्ति व आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में लगाऊंगा। जब यह मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हो गया है तो अब विलंब न करके पूर्ण तत्वदर्शी संत की खोज करें। उनको गुरु बनाकर उनसे दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत सच्ची भक्ति व आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होकर अपना उद्धार करने लिए तत्पर हो जाएं।

अशोक वाजपेयी

तथ्य-कथ्य

कब किसने हासिल किया 3 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्थाएं- यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन और जापान

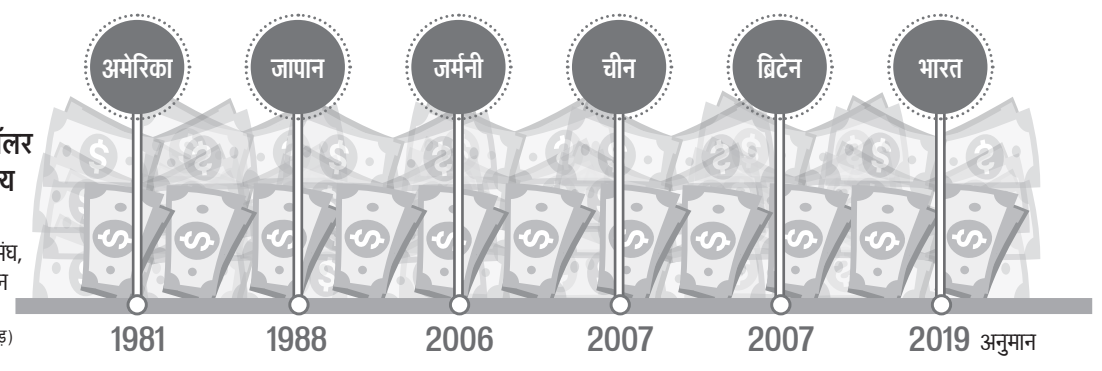

(एक ट्रिलियन = एक लाख करोड़)

हवा, पानी और बिजली से बना भोजन

मुकुल व्यास

गेहूं के आटे जैसे पाउडर वाले इस खाद्य उत्पाद के लिए खेती की दरकार नहीं। दो वर्षों में यह बाजार में दस्तक दे सकता है

सिर्फ पानी, बिजली और हवा से खाद्य पदार्थ बनाने की बात सुनने में कुछ अजीब लगती है। पेड़-पौधे यह काम कुदरती तौर पर करते हैं, लेकिन इसे कृत्रिम रूप से करना एक बड़ी तकनीकी चुनौती है। फिनलैंड की एक कंपनी का दावा है कि उसने पानी, हवा और बिजली से एक ऐसा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ बनाया है जिसका स्वाद गेहूं के आटे जैसा है। कंपनी दो साल में इसे बाजार में पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसकी लागत पांच यूरो (करीब 384 रुपये) प्रति किलो बैठेगी। फिनलैंड की सोलर फूड्स नामक कंपनी का कहना है कि वह वर्ष 2021 में इस खाद्य उत्पाद का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने से पहले इस साल यूरोपीय संघ से फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। कंपनी मंगल मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति करना चाहती है।

इसके लिए वह यूरोपीय स्पेस एजेंसी से बात कर रही है। फिनिश कंपनी ने फिनलैंड के वीटीटी टेक्निकल रिसर्च सेंटर और लेप्पीनरांटा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोध के आधार पर इस खाद्य उत्पाद की विधि विकसित की है। कंपनी द्वारा विकसित आटे जैसे पाउडर का नाम 'सोलेन' रखा गया है। थ्रीडी प्रिंटिंग के जरिये इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है या इसे किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाया जा सकता है। इसे बनाने की विधि बीयर बनाने की प्रक्रिया जैसी है। सोलेन बनाने के लिए जीवाणुओं को पानी में रखा जाता है और उन्हें कार्बन डाईऑक्साइड और हाइड्रोजन के बुलबुलों की खुराक दी जाती है जो बिजली के प्रयोग द्वारा पानी से मुक्त होते हैं। ये जीवाणु प्रोटीन का निर्माण करते हैं जिसे सुखाकर पाउडर तैयार किया जाता है।

कंपनी के एक प्रमुख अधिकारी पासी वाइनिक्का का कहना है कि यह एकदम नई किस्म का खाद्य पदार्थ है जो बाजार में फिलहाल उपलब्ध सभी किस्म के खाद्य पदार्थों से एकदम भिन्न है। इसके लिए कृषि की आवश्यकता नहीं है। इसमें जमीन और पानी का कोई अपव्यय नहीं होता। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा विकसित पदार्थ दुनिया का सर्वाधिक पर्यावरण-अनुकूल प्रोटीन है। दुनिया में उपभोग की जाने वाली तीन-चौथाई कैलोरी अभी 12 वनस्पति और पांच प्राणि प्रजातियों से प्राप्त होती है। इस समय दुनिया में एक-चौथाई कार्बन का बोझ खाद्य उत्पादन की वजह से है और भविष्य में यह और बढ़ेगा।

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सदी के मध्य तक दुनिया के खाद्यान्न उत्पादन में 50-70 प्रतिशत तक वृद्धि की आवश्यकता होगी। दुनिया की करीब आधी भूमि का उपयोग खेती के लिए होता है। वाइनिक्का का कहना है कि सोलेन पाउडर का उपयोग किसी खाद्य पदार्थ के हिस्से के रूप में किया जा सकता है। इस पाउडर से ऐसे फाइबर भी निर्मित किए जा सकते हैं जो देखने में ब्रेड या मीट जैसे होंगे। फिनलैंड के वीटीटी सेंटर के वैज्ञानिक जुहा-पेक्का पिटकानेन का कहना है कि भविष्य में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग रेगिस्तानी और सूखाग्रस्त इलाकों में किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ऊर्जा की खपत की दृष्टि से बिजली से खाद्य वस्तु तैयार करने की प्रक्रिया पौधों में प्रकाश-संश्लेषण की तुलना में दस गुना अधिक किफायती है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

अपनों को फिट कराने की मुहिम

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो नेता तमाम कोशिशों के बावजूद मंत्री पद पाने से महरूम रह गए, वे अब अपने निजी स्टाफ को दूसरे मंत्रियों के साथ खपाने की मुहिम में लगे हैं। वहीं कई दिग्गज ऐसे भी हैं जिन्हें मंत्रिमंडल के अगले फेरबदल का बेसब्री से इंतजार है। वे तो इस उम्मीद में बैठे हैं कि अगली बार उनका नंबर फिर से लग सकता है। पिछली मोदी सरकार में एक बड़ा मंत्रालय संभाल चुके नेता ने अभी हाल में मौजूदा सरकार में एक मंत्री को फोन करके कहा कि चूंकि उनके पास तीन मंत्रालय का जिम्मा है इसीलिए वह उनके कुछ स्टाफ को अपने यहां रख लें। बताते हैं कि मंत्री जी ने तुरंत अपने दल के वरिष्ठ नेता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनके कई लोगों को अपने पास रख लिया। ऐसे ही मोदी सरकार-एक में कई अहम मंत्रालयों को संभाल चुके नेताजी ने चुनाव हारने के बाद अपने निजी स्टाफ के लिए अपने ही राज्य के ही नेता से निवेदन किया और खुद दरख्वास्त लेकर पहुंच गए और वहां उनकी बातों पर ध्यान भी दिया गया। मगर मौजूदा सरकार में सभी मंत्री इतने दरियादिल नहीं हैं। कुछ मंत्रियों ने अपने साथियों की ऐसी गुजारिशों को खास तवज्जो नहीं दी। अपनी मांगें ठुकराए जाने से आहत इन मायूस पूर्व मंत्रियों ने अपनी बात अब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक पहुंचाने का मन बनाया है। अब देखना यही होगा कि वहां उनकी सुनवाई पर क्या होता है।

समझ का असमंजस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से कई बार मेजें थपथपाई गईं। मगर कई सांसद ऐसे भी देखे गए जो मेज थपथपाने के लिए मानो किसी के इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हों। एक तो बजट का भाषण, वह भी अंग्रेजी में। इसलिए कई बार कुछ सांसदों को मेज थपथपाने के लिए आसपास के सांसदों से भी मदद मिली। वैसे कई सांसदों की नजर तो सदन में बैठे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह पर बनी रही। मेज थपथपाने के लिए इन सांसदों के लिए अपने नेताओं का मेज थपथपाना ही किसी इशारे से कम नहीं था।

चढ़ने लगा सियासी रंग

कूटनीति की दुनिया का अंदाज राजनीति के मिजाज से एकदम जुदा होता है, मगर नए विदेश मंत्री एस जयशंकर बहुत तेजी से राजनीति के तौर-तरीकों से वाकिफ होते जा रहे हैं। गुजरात से राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाने के कुछ पल बाद उन्होंने सबसे पहले गुजराती भाषा में सभी का धन्यवाद दिया। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में भी धन्यवाद दिया, लेकिन गुजराती भाषा में किए गए उनके ट्वीट को ज्यादा पसंद किया गया। कहने की जरूरत नहीं कि गुजरात यह गर्व करने लगा है कि गृह मंत्री के अलावा विदेश मंत्री भी उनके राज्य से हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता भी गुजरात से ही है। यही नहीं संसद में जयशंकर के तेवर बदलने लगे हैं। मसलन, अब सत्ता पक्ष के दूसरे सदस्य जब अपनी बात कहकर विपक्षी दलों पर हमला करते हैं तो जयशंकर भी दूसरे सांसदों की तरह मेजें थपथपाने लगे हैं।

बड़े बंगले की ख्वाहिश

इस बार लोकसभा में ढाई सौ से ज्यादा नए सांसद पहुंचे हैं और हर किसी की ख्वाहिश यही है कि दिल्ली में उसे अच्छे से अच्छा बंगला मिल जाए। इस कारण बंगला आवंटन करने वाली आवासीय समिति की परिक्रमा तेज हो गई है और हर किसी के पास खुद के लिए बड़ा बंगला पाने का अलहदा तर्क है। एक महिला सांसद जो एक बाहुबली की पत्नी को हराकर संसद पहुंची हैं, उनकी दलील है कि सुरक्षा के लिहाज से उन्हें तय मानक से बड़ा बंगला दिया जाए। तो किसी के पास यह तर्क है कि वह क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं और इसलिए ऐसा आवास चाहिए जहां 25-50 अतिरिक्त लोग भी ठहर सकें। जो नई सरकार में मंत्री नहीं हैं वे टाइप-सात बंगले में जाने के लिए थोड़ा वक्त चाहते हैं। ऐसे में आवासीय समिति के अध्यक्ष खुद सांसत में फंस गए हैं जो खुद अपने लिए बड़े बंगले के जुगाड़ में हैं, लेकिन बंगले के लिए हो रही मारामारी को देखते हुए अपने अरमानों को ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं ताकि दूसरों के सामने नैतिकता की दुहाई दे सकें।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन.संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चय